सम्पादक की कलम से

कड़कती बिजली और गड़गड़ाते हुए बादलों की आवाज से डरे चिड़िया के बच्चों ने मां से कहा कि यह सब कब खत्म होगा ? खुद भी सहमी चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे दबाते हुए कहा, सब ठीक हो जायेगा बच्चों मैं हूँ ना. यही हाल अब भ्रष्ट नेता और अफसर का है क्योंकि जब भी कोई आर्थिक घोटाला उजागर होता है या उसका भण्डाफोड़ होता है तो वे उनके मातहत कार्यरत लोगों के डर को समझते है और उन्हें केवल इसी प्रकार का दिलासा देते है. जबकी वे खुद भी इसी डर से डरे हुए होते है.

शिक्षा हो या स्वास्थ्य इन मामलों में भारत दुनिया के देशों में बहुत पिछड़ा हुआ है. मगर भारत का नाम भ्रष्ट देशों की सूचि में अव्वल नम्बर पर है. आज हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर दो बेहद ईमानदार नेता बैठे है और वे इसके बारे में समय समय पर इसके निवारण के उपाय के रूप में कानून बनाते है और उन्हें सार्वजनिक प्रचार तंत्र के माध्यम से प्रसारित भी किया जाता है लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार का तंत्र यथावत बरकरार है. नेता हो या अफसर जब भी वे भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाते है लेकिन इस मामलों में जाँच के दौरान झूठे सबूत उनके ही किसी अधिकारी द्वारा जाँच ऐजेन्सी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है. ऐसा इसलिये करना जरूरी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि इन लोगों को सजा होगी तो अगला नम्बर उन्हीं का होगा. और इस तरह प्रकरण को कमजोर कर दिया जाता है और अफसर हो या नेता अधिकांश मामलों में निर्दोष छूट जाते है. और यही से शुरूवात होती है हमारे देश के पतन की.

आज हर आदमी जिसे भ्रष्टाचार करने का मौका मिला है उसने उस मौके का भरपुर फायदा उठाया है. विश्वविजेता सिकंदर हो या नेपोलियन जिन्होंने अकुत दौलत एकत्रित की. क्या वे इस दौतल को अपने साथ ले जा पाये ? नहीं . सिकंदर ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने मंत्रीयों को आदेश दिया था कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसके हाथों को ताबुत से बाहर रखा जाये. ऐसा करने का एकमात्र कारण यही था कि वह दुनियाँ को संदेश देना चाहता था कि मैंने अथाह दौलत एकत्रित करने के लिये जीवन भर युद्ध किया लेकिन जब मृत्यु हुई तो वह खाली हाथ ही था. अपने साथ कोई दौलन नहीं ले जा पाया.

लेकिन जो भ्रष्टाचार से लड़ने की कोशिश करते है. उनके सीने गोलियों से छलनी कर दिये जाते है. समाचार आते है पढते है चौराहो पर उसके बारे में तर्क वितर्क होता है और सब इन बातों को भुल जाते है. अग्रेजी में इसी को जन्मजात दौर्बल्य कहा जाता है. जिन लोगों के मस्तिष्क में इस प्रकार की उलजलूल बातों के अलावा कुछ नहीं है उन्हीं को जड़बुद्धि कहा जाता है. त्रिपुंड दाई और लगाना चाहिए अथवा बाई और, चंदन माथे पर लगाना चाहिए या आरती दो बार उतारनी चाहिये अथवा बार-बार, उस तांत्रिक या महात्मा ने यह कह दिया वह अटल ही है इन प्रश्नों को लेकर जो दिन रात माथा पच्ची किया करते हैं उन्हीं का नाम भाग्यहीन है और इसीलिए हम लोग श्रीहीन हो गये और पश्चिम के लोग दिग्विजयी.

आज देश के हर नागरिक का कर्तव्य है वह देश के लिये कुछ न कुछ अवश्य करे. स्वतंत्र बनों,स्वतंत्र बुद्धि से काम लेना सीखों. लोकहित एवं ऐसे कार्यो में आत्म-विनियोग करो जिससे कि देश का कल्याण हो सके चाहे अपने को नरक में ही क्यों न जाना पड़े परंतु देश का हित अवश्य सोचे. प्रत्येक देश के नागरिक इतना मानसिक रूप से दरिद्र भी नहीं है कि वह किसी-न-किसी रूप में देशहित में कोई कार्य नहीं कर पाये. यदि हम देश का कल्याण चाहते है तो जैसे अग्नि चारो और फैलती है उसी तरह हमें भी देश के हित में चारों और अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिये.

पादरियों का सियासी पत्राचार मोदी के खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश

यह विचार करने की बात है कि चर्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या दिक्कत हो रही है कि पादरियों ने सियासी पत्राचार प्रारंभ कर दिया है। ईसाई संप्रदाय में प्रमुख स्थान रखने वाले आर्कबिशप (प्रधान पादरी) भाजपा सरकार के विरुद्ध खुलकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले गुजरात चुनाव में आर्कबिशप थॉमस मैकवान ने चिट्ठी लिखकर ईसाई समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे गुजरात चुनाव में %राष्ट्रवादी ताकतों% को हराने के लिए मतदान करें। इसके बाद मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए चर्च सक्रिय हुआ। कर्नाटक भी चर्च की राजनीति से अछूता नहीं रहा। अब दिल्ली के आर्कबिशप अनिल काउटो ने राजधानी के सभी चर्च के पादरियों को पत्र लिखकर अपील की है- %अपने देश और इसके नेताओं के लिए हर समय प्रार्थना करना हमारी पवित्र प्रथा है, लेकिन जब हम आम चुनावों की तरफ बढ़ते हैं तो यह प्रार्थना बढ़ जाती है। अगर हम 2019 की ओर देखें तो तब हमारे पास नई सरकार होगी और चलिए हम अपने देश के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं।%

आर्कबिशप के इस पत्र पर राजनीति प्रारंभ हो गई है, जो कि स्वाभाविक ही है। जब खुलकर चर्च सियासत करेगा, तो राजनीतिक चर्चा तो होनी ही है। किंतु, आश्चर्य की बात यह है कि पादरी की चिट्ठी पर वह लोग बचाव की मुद्रा में खड़े हैं, जो धर्म को राजनीति से दूर रखने की वकालत करते हैं। कथित प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने चर्च की सियासत पर एकदम से मुँह सिल लिया है। उनमें से कुछ बोल भी रहे हैं, तो चर्च के समर्थन में। वह इस चिट्ठी को सामान्य बता रहे हैं। जबकि आर्कबिशप की यह चिट्ठी सीधेतौर पर सियासत में धार्मिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहित कर रही है। सोचिए, यदि ऐसी ही कोई चिट्ठी किसी हिंदू धर्म के प्रमुख ने लिख दी होती, तब कैसा हंगामा खड़ा होता? जो लोग आज चर्च की राजनीति को आड़ दे रहे हैं, वही हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा रहे होते। हिंदू धर्म पर टीका-टिप्पणी करने के लिए वह सदैव अवसर की ताक में बैठे रहते हैं। किंतु, जैसे ही बात दूसरे धर्म की आती है, सेक्युलर जमात मुँह में दही जमा कर बैठ जाती है। बात ईसाइयत और चर्च की निंदा करने की नहीं है, बल्कि राजनीति में इस प्रकार के सीधे हस्तक्षेप को रोकने की है।

आर्कबिशप अनिल आउटो ने अपने पत्र में भारत की राजनीतिक स्थिति को अशांत बताया है। काउटो ने लिखा है कि मौजूदा अशांत राजनीतिक माहौल संविधान में निहित हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने के लिए खतरा बन गया है। काउटो के पत्र की यह भाषा सीधे तौर पर वर्तमान भारत सरकार, भारतीय पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर हमला है। आखिर पंथनिरपेक्ष तानेबाने पर कौन-सा खतरा आ गया है? भाजपा सरकार के आने के बाद से माना जा रहा है कि धर्मांतरण की प्रक्रिया में चर्च को बाधा आ रही है। भारत के वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले भोले-भाले हिंदुओं का धर्मांतरण अब चर्च के लिए कठिन हो रहा है। क्या इसलिए चर्च को पीड़ा हो रही है?

प्रश्न यह भी है कि आर्कबिशप 2019 में %नई सरकार% लाने के लिए प्रार्थना और उपवास किसने कहने पर प्रारंभ कर रहे हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक ताकतों का हाथ है या वेटिकन सिटी का हस्तक्षेप। भारत में इन बिशपों की नियुक्ति सीधे पोप करते हैं। यह बिशप पोप के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए माना जा सकता है कि पोप के कहने पर भारत के आर्कबिशपों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी ताकतों को हराने की योजना पर काम करना प्रारंभ किया है। अब इसमें भी विचार करने की दो प्रमुख प्रश्न मन में आते हैं। पोप की क्या रुचि है? पोप यानी चर्च, क्यों राष्ट्रवादी ताकतों को हरा कर अपने मनमुताबिक नई सरकार लाना चाहता है? एक, क्या मतांतरण भर पोप की चिंता है? दो, क्या चर्च भारत के राजनीतिक दलों के आग्रह पर ईसाई वोट का ध्रुवीकरण कर रहा है?

देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसके मुखिया के तार चर्च से जुड़ते हैं। यह आशंका इसलिए है क्योंकि आर्कबिशप की यह चिट्ठी ऐसे समय में आई है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रोकने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। भाजपा विरोधी राजनेता यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के विजयी रथ को थामने के लिए हिंदू मत को विभाजित करना और बाकी के संप्रदायों के मत का ध्रुवीकरण करना आवश्यक है। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार के मंत्री डॉ. एमबी पाटिल का एक पत्र मीडिया के माध्यम से सामने आया। यह पत्र उन्होंने जुलाई, 2017 में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा गया था। पत्र में डॉ. पाटिल ने स्पष्ट लिखा है कि भाजपा को हराना है तो %हिंदुओं को तोड़ना होगा।% साथ ही, ईसाइयों और मुसलमानों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर एकजुट करना होगा। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा है कि हिंदुओं को बाँटने और ईसाई-मुस्लिम को अपने पक्ष में करने का प्रयास उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इसमें कर्नाटक कांग्रेस ने %ग्लोबल क्रिश्चियन कॉउंसिल% और %वर्ल्ड इस्लामिक आर्गेनाईजेशन% से मदद ली है। पाटिल ने लिखा है कि हिंदुओं को जाति (पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति) और धर्म में बाँट कर उसे कमजोर किया जा सकता है। कर्नाटक चुनाव में देश ने देखा भी कि किस प्रकार कांग्रेस ने हिंदुओं को जाति और धर्म (लिंगायत समुदाय को अलग धर्म की मान्यता) के आधार पर बाँट कर कमजोर करने का प्रयास किया। %बाँटो ओर राज करो% की नीति का लाभ भी कांग्रेस को मिला है। संभव है कि चर्च की मदद से वह अपनी आगे की राह को सुगम करना चाहती है।

बहरहाल, जो भी हो, अब जब चर्च खुलकर राजनीति के मैदान में उतर आया है, तब देखना होगा कि हिंदू समाज क्या विचार करता है? मतदान के संदर्भ में उसकी विचार प्रक्रिया पर पादरी की %चिट्ठी सियासत% का क्या असर होगा? बहरहाल, चुनाव आयोग और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भारतीय लोकतंत्र में चर्च के अनुचित हस्तक्षेप और उसकी राजनीतिक गतिविधि पर संज्ञान लेना चाहिए। यह भारतीय संविधान और न्यायालय की भी अवमानना है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी धार्मिक नेता अपने समुदाय के लोगों को किसी उम्मीदवार या पार्टी के समर्थन या विरोध में मतदान करने के लिए नहीं कह सकता। किंतु, यहाँ चर्च का आचरण भारत के संविधान के विरुद्ध है। यहाँ पादरी की चिट्ठी से चर्च की नीयत भी उजागर हुई है।